[श्री सत्पाल मलिक]

फसल को उसे इधर-उधर ले जाकर बेचने पर पाबंदी लगा देते है। हरियाणा की मंडी में अच्छा दाम है। हमारे यहां कम है और आपने पाबंदी भी लगाई है, कल हम किसान लोग उसको तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे ज्यादा अन्यायपूर्ण और कोई कानून नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें तत्काल हस्तक्षेप करे और किसान को अपनी फसल आजादी के साथ देश में जहां वह चाहे उसे बेचने का अधिकार दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

Bungling in distribution of Loans by the Nationalised Banks.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय आज मैं जिस समस्या की ओर सदन और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं और वह बहुत गंभीर समस्या है। जिन दिनों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उन दिनों एक सपना था कि गांव के लोगों को, गरीबों को, ऋण मिलेगा, कर्ज मिलेगा और आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आज राष्ट्रीयकरण होने के करीब-करीब 18 वर्ष बाद जो बैंकों की स्थिति है वह बहुत ही भयावह है। मेरे यहां बिहार में महोदय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई कर्ज देने के पहले बैंकर 10 परसेंट काट लेता है। बिना दस परसेंट लिए हुए एक पैसा नहीं देता है। बहुत से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग ऋण मंजूर कराते हैं और इंडस्ट्री विभाग से गवर्नमेंट से सब प्रोसेस हो जाता है तो भी एक साल, डेढ़ साल, छः महीने से कम में तो किसी का निष्पादन होता ही नहीं है। यही उसका पक्का सबूत है कि जब पिटीशन सारा प्रोसेस हो गया और लोन सेंकसन करने के लिए आ गया गवर्नमेंट से आपके यहां, तब छह महीना, साल भर, डेढ़ साल क्यों रुका रहता हैं? तो 10 परसेंट तो हमारे यहां जो बैंकर लेता है वह बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 15 परसेंट, 20 परसेंट भी लेता है। खासकर आई० आर० डी० पी० जो योजना है, जिसमें भैंस खरीदवाने के लिए या टमटम खरीदवाने के लिए, छोटी दुकान के लिए पैसा देना है, उसमें तो निश्चित तौर पर 15 परसेंट, 20 परसेंट लोन का ले लेते हैं और कहीं-कहीं तो गहना बेचकर लोगों को देना पड़ता है।

अभी मैंने 30 तारीख को प्रदर्शन कराया था प्रखंड में, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को मैंने बुलाया भीड़ में। आए। मैंने पूछा—तुम कितने दिन से यहां हो? बोले—एक साल से। कहा—कितना कर्ज बांटा? कहा—65 हजार। मैंने कहा—65 हजार जब बांटा तो तुमको तो इसी आधार पर डिसमिस कर देना चाहिए, एक साल में सिर्फ 65 हजार तुमने कर्जा बांटा। क्यों कम बांटा? और उसने कहा कि 268 पिटीशन क्लीयर होकर रखी हुई हैं, दे नहीं रहे। तो उसके मुंह पर लोगों ने कहा जनता में से उठकर, कि हमने गहना बेचकर आपको पैसा दिया है कि नहीं? उसका मुंह फक हो गया। यह मैं एक मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूं। लेकिन महोदय, यह तो सारे बिहार के हर बैंक में बिना अपवाद के, बिना एक्सेप्शन के विद्यमान है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री इस ओर ध्यान दें। चूंकि यह भारत सरकार का उपक्रम है इसलिए गृह मंत्रालय की भी जिम्मेवारी है कि कुछ फ्लाइंग स्क्वायड आप तैयार करें, बैंकों में इस चीज को पकड़ने के लिए। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है बैंक का, वह पांच लाख देना है लोन दस लाख देना है स्माल स्केल इंडस्ट्री को तो उसमें से 10 परसेंट के हिसाब से जोड़ लीजिए, वह ले लेता है यानी दस लाख दिया तो उसमें से एक लाख वह ले लेता है। इसलिए मैं चाहता हूं महोदय, कि फाइनेंस मिनिस्टरी हर जिले में एक फ्लाइंग-स्क्वायड कायम करे।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं... **(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : नहीं-नहीं, उदाहरण नहीं। पांच मिनिट हो गए, खत्म कीजिए आप प्लीज। यह स्पेशल मेंसन है, पांच मिनिट हो गए आपको और ज्यादा क्या बोलेंगे आप?

श्री राम अवधेश सिंह : तो मैंने रीजनल मैनेजर पटना, पंजाब नेशनल बैंक से बातचीत की। मैंने उससे कहा ऐसी-ऐसी शिकायत है। तो वह कहता है कि हमको शिकायत दीजिए। मैंने कहा— मैं तो दूंगा, लेकिन आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आप अपनी मशीनरी को चेक करें। आपके जो काम करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसको आप चेक करें, यह आपकी भी अपनी ड्यूटी बनती है।

मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे और मांग करता हूं कि हर जिले में एक फ्लाइंग स्क्वायड बैंक की ओर से और एक फ्लाइंग-स्क्वायड होम-मिनिस्टरी की ओर से भारत सरकार का बने ताकि ऐसे लोगों को पकड़े और जिले में दो चार ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके बंद करे तो एक तरह से जनता की कुछ सेवा होगी क्योंकि पैसा उनको मिलता ही नहीं है।

आपको बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दिया।

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 6th November, 1987 allotted time for Government Legislative and other Business as follows:—

Business	Time allotted
1 Consideration and passing of the following Bills:-	
(a) The Authorised Translations (Central Laws) Amendment Bill, 1987.	1 hr.
(b) The All India Council for Technical Education Bill, 1987.	2hrs.
(c) The Equal remuneration (Amendment) Bill, 1987.	2 hrs.
2 Discussion on the resolution seeking disapproval of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Ordinance, 1987 and consideration and passing of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 1987.	2 hrs.
3 Discussion on the resolution seeking disapproval of the representation of the people (Amendment) Ordinance, 1987 and consideration and passing of the representation of the People (Amendment) Bill, 1987.	2 hrs.
4 Consideration and passing of the Auroville (Emergency Provisions) Amendment Bill, 1987.	2 hrs.
5 Discussion on the resolution regarding continuance of President's Rule in the State of Punjab.	1 day i.e., on Monday, the 9th November, 1987.

The Committee recommended that the House should sit upto 6.00 P.M. daily and beyond 6.00 P.M. as and when necessary, for the transaction of Government Business, from Monday, the 9th November, 1987.

Now the House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 9th November, 1987.

The House then adjourned at thirty six minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 9th November, 1987.